IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 4, January 2026 Impact Factor: 7.67

जाति, लिंग और वर्ग के संदर्भ में शिक्षा में असमानताओं का समाजशास्त्रीय विश्लेषण

विश्राम मीना[1] and डॉ. **नेहा यादव**[2]

[1]शोधार्थी, शिक्षा शास्त्र - विभाग

[2]सह - प्राध्यापक, शिक्षा शास्त्र - विभाग

सनराइज़ विश्वविद्यालय अलवर, राजस्थान

सारांश

शिक्षा किसी भी समाज के विकास, सामाजिक गतिशीलता और समान अवसरों की आधारशिला मानी जाती है। तथापि भारतीय समाज में शिक्षा तक पहुँच और उसकी गुणवत्ता जाति, लिंग तथा वर्ग जैसे सामाजिक कारकों से गहराई से प्रभावित होती है। यह समीक्षा-पत्र शिक्षा में विद्यमान असमानताओं का समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन का उद्देश्य यह समझना है कि सामाजिक संरचना किस प्रकार शैक्षिक अवसरों के वितरण को प्रभावित करती है। प्रस्तुत शोध में विभिन्न समाजशास्त्रीय सिद्धांतों संरचनात्मक क्रियावाद, संघर्ष सिद्धांत, तथा पियरे बोरदियो के सांस्कृतिक पूँजी सिद्धांत के माध्यम से शैक्षिक विषमताओं की व्याख्या की गई है।

मुख्य संकेतक: - शिक्षा, असमानता, जाति, लिंग, वर्ग, समाजशास्त्र।

परिचय

भारतीय समाज विविधताओं से परिपूर्ण है, जहाँ जाति, लिंग और वर्ग सामाजिक संगठन के प्रमुख आधार हैं। शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का माध्यम माना जाता है, परंतु व्यवहार में यह समान रूप से उपलब्ध नहीं है। अनेक अध्ययन संकेत करते हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को शिक्षा में समान अवसर नहीं मिलते (देसाई और कुलकर्णी,2018)। इसी प्रकार लड़कियों की शिक्षा में भी कई सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएँ विद्यमान हैं।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 4, January 2026 Impact Factor: 7.67

शिक्षा और समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य

शिक्षा और समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत शिक्षा को केवल ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि इसे समाज की संरचना, संस्कृति, मूल्यों, परंपराओं और सत्ता-संबंधों से गहराई से जुड़ी एक सामाजिक संस्था माना जाता है। समाजशास्त्र शिक्षा का अध्ययन इस दृष्टि से करता है कि शिक्षा किस प्रकार समाज में समानता या असमानता को उत्पन्न, बनाए या परिवर्तित करती है। शिक्षा समाजीकरण का प्रमुख माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक मानदंडों, आचरणों, सांस्कृतिक मूल्यों और भूमिकाओं को सीखता है। इमाइल दुर्खीम के अनुसार शिक्षा समाज का वह साधन है जिसके माध्यम से समाज अपनी सामूहिक चेतना को नई पीढ़ी तक पहुँचाता है और सामाजिक एकता को बनाए रखता है।

विद्यालय केवल पाठ्य ज्ञान देने का स्थान नहीं, बल्कि सामाजिक अनुशासन, नैतिकता और सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने वाला संस्थान है। इस दृष्टिकोण में शिक्षा सामाजिक स्थिरता और एकीकरण का माध्यम है। दूसरी ओर कार्ल मार्क्स और संघर्षवादी समाजशास्त्रियों के अनुसार शिक्षा समाज में विद्यमान वर्गीय असमानताओं को पुनरुत्पादित करती है। उनका मत है कि शिक्षा व्यवस्था शासक वर्ग के हितों की रक्षा करती है और ऐसी विचारधारा विकसित करती है जिससे निम्न वर्ग अपनी अधीनता को स्वाभाविक मानने लगता है। उदाहरणस्वरूप निजी और सरकारी विद्यालयों के बीच संसाधनों का अंतर वर्गीय विषमता को और गहरा करता है। उच्च वर्ग के बच्चों को बेहतर विद्यालय, प्रशिक्षित शिक्षक, तकनीकी संसाधन और अनुकूल वातावरण प्राप्त होता है, जबकि निम्न वर्ग के बच्चे सीमित सुविधाओं वाले विद्यालयों में अध्ययन करते हैं, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता प्रभावित होती है।

पियरे बोरदियो ने सांस्कृतिक पूँजी की अवधारणा देकर स्पष्ट किया कि परिवार की सामाजिक पृष्ठभूमि शिक्षा में सफलता को प्रभावित करती है। जिन परिवारों में पुस्तकें, भाषा कौशल, सांस्कृतिक संसाधन और शैक्षिक वातावरण उपलब्ध होता है, वहाँ के बच्चे विद्यालयी शिक्षा में अधिक सफल होते हैं। इसके विपरीत वंचित समुदायों के बच्चे सांस्कृतिक पूँजी के अभाव में पीछे रह जाते हैं। इस प्रकार शिक्षा तटस्थ नहीं रहती, बल्कि सामाजिक असमानताओं को वैधता प्रदान करने लगती है। मैक्स वेबर ने शिक्षा को सामाजिक प्रतिष्ठा और अवसरों से जोड़ा तथा बताया कि शिक्षा सामाजिक गतिशीलता का माध्यम बन सकती है, किंतु अवसरों की समान उपलब्धता के बिना यह संभव नहीं है। भारतीय संदर्भ में शिक्षा का समाजशास्त्रीय अध्ययन विशेष महत्व रखता है क्योंकि यहाँ जाति, लिंग, वर्ग, भाषा, क्षेत्र और धर्म जैसे अनेक कारक शिक्षा की पहुँच और गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। जाति व्यवस्था भारतीय शिक्षा प्रणाली में ऐतिहासिक रूप से गहरे पैठी रही है।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 4, January 2026 Impact Factor: 7.67

लंबे समय तक निम्न जातियों को औपचारिक शिक्षा से वंचित रखा गया, जिसका प्रभाव आज भी दिखाई देता है। अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों को विद्यालयों में भेदभाव, सामाजिक बहिष्कार और संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा केवल व्यक्तिगत योग्यता का परिणाम नहीं, बल्कि सामाजिक संरचना से निर्धारित अवसरों का प्रतिफल है। लिंग आधारित असमानताएँ भी शिक्षा के समाजशास्त्रीय विश्लेषण का महत्वपूर्ण पक्ष हैं। अनेक समाजों में लड़कियों की शिक्षा को अभी भी गौण माना जाता है। बाल विवाह, घरेलू श्रम, पितृसत्तात्मक सोच और सुरक्षा संबंधी चिंताएँ लड़कियों की शैक्षिक प्रगति में बाधा डालती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में माध्यमिक स्तर पर लड़कियों का विद्यालय छोड़ना अधिक देखा जाता है। समाजशास्त्र यह समझने का प्रयास करता है कि किस प्रकार सामाजिक मान्यताएँ और लैंगिक भूमिकाएँ शिक्षा में भेदभाव उत्पन्न करती हैं। इसी प्रकार आर्थिक वर्ग भी शिक्षा के अवसरों को निर्धारित करता है। उच्च आय वर्ग के परिवार अपने बच्चों को निजी विद्यालयों, कोचिंग संस्थानों और डिजिटल शिक्षा संसाधनों तक पहुँच दिला सकते हैं, जबकि गरीब परिवारों के बच्चे अक्सर विद्यालय छोड़कर श्रम में लग जाते हैं।

कोविड-19 महामारी के दौरान डिजिटल विभाजन ने यह असमानता और स्पष्ट कर दी, जब अनेक गरीब विद्यार्थियों के पास ऑनलाइन शिक्षा के लिए मोबाइल, इंटरनेट या कंप्यूटर उपलब्ध नहीं थे। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य यह भी बताता है कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का प्रभावी साधन हो सकती है। यदि शिक्षा समावेशी, समान और न्यायपूर्ण हो तो यह सामाजिक गतिशीलता बढ़ा सकती है तथा हाशिए के समुदायों को सशक्त बना सकती है। डॉ. भीमराव आंबेडकर ने शिक्षा को सामाजिक मुक्ति का हथियार माना और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए इसे आवश्यक बताया।

आधुनिक भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना, छात्रवृत्ति योजनाएँ तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी नीतियाँ इसी दिशा में प्रयास हैं। फिर भी केवल नीतियाँ पर्याप्त नहीं हैं; समाजशास्त्रीय दृष्टि से यह आवश्यक है कि सामाजिक मानसिकता, संस्थागत व्यवहार और सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों में भी परिवर्तन आए। शिक्षा का पाठ्यक्रम, शिक्षक-छात्र संबंध, विद्यालयी संस्कृति और मूल्यांकन प्रणाली भी सामाजिक संरचनाओं से प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए पाठ्यपुस्तकों में यदि केवल प्रभुत्वशाली वर्ग की संस्कृति और इतिहास को स्थान दिया जाए, तो वंचित समुदाय स्वयं को शिक्षा से असंबद्ध महसूस करते हैं। इसलिए बहुसांस्कृतिक और समावेशी पाठ्यचर्या आवश्यक है।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 4, January 2026 Impact Factor: 7.67

शिक्षा का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य यह स्पष्ट करता है कि शिक्षा समाज से अलग कोई स्वतंत्र संस्था नहीं, बल्कि समाज की संरचना, शक्ति संबंधों और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं का प्रतिबिंब है। यह समानता का साधन भी बन सकती है और असमानता का पुनरुत्पादक भी। इसीलिए शिक्षा का विश्लेषण केवल विद्यालयों की संख्या, साक्षरता दर या परीक्षा परिणामों से नहीं, बल्कि इस प्रश्न से किया जाना चाहिए कि समाज के विभिन्न वर्गों को शिक्षा में कितनी समान भागीदारी और अवसर प्राप्त हैं। यही दृष्टिकोण शिक्षा को अधिक न्यायपूर्ण, लोकतांत्रिक और समावेशी बनाने की दिशा प्रदान करता है (दुर्खीम, 2010; बुर्दियू, 2012; देसाई और कुलकर्णी, 2018)।

समाजशास्त्रीय दृष्टि से शिक्षा केवल ज्ञानार्जन का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक संरचना के पुनरुत्पादन का उपकरण भी है।

1. संरचनात्मक क्रियावादी दृष्टिकोण

दुर्खीम के अनुसार शिक्षा समाजीकरण की प्रक्रिया है, जो सामाजिक एकता बनाए रखती है।

2. संघर्ष सिद्धांत

मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षा व्यवस्था समाज में विद्यमान वर्गीय असमानताओं को बनाए रखती है।

3. सांस्कृतिक पूँजी सिद्धांत

बोरदियो (2012) के अनुसार उच्च वर्ग के बच्चों को सांस्कृतिक संसाधनों का लाभ मिलता है, जिससे वे शिक्षा में बेहतर प्रदर्शन करते हैं।

जाति और शिक्षा में असमानता

भारतीय समाज में जाति व्यवस्था एक ऐतिहासिक सामाजिक संरचना रही है, जिसने व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, आर्थिक अवसरों और शैक्षिक पहुँच को गहराई से प्रभावित किया है। शिक्षा, जिसे सामाजिक परिवर्तन और समान अवसरों का सबसे प्रभावी माध्यम माना जाता है, भारतीय संदर्भ में लंबे समय तक जातिगत विभाजन से मुक्त नहीं रही। जाति और शिक्षा के संबंध का विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि समाज के विभिन्न जातीय समूहों के बीच शिक्षा की उपलब्धता, गुणवत्ता, पहुँच तथा उपलब्धियों में व्यापक असमानताएँ विद्यमान हैं।

प्राचीन भारतीय समाज में शिक्षा पर उच्च जातियों, विशेषकर ब्राह्मणों, का नियंत्रण था, जबकि शूद्रों और तथाकथित अछूत वर्गों को औपचारिक शिक्षा से वंचित रखा जाता था। यह परंपरा आधुनिक भारत में

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 4, January 2026 Impact Factor: 7.67

संवैधानिक समानता के बावजूद अनेक रूपों में बनी रही है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के बच्चों को विद्यालयों में प्रवेश तो मिल गया, परंतु व्यवहारिक स्तर पर उन्हें अभी भी भेदभाव, सामाजिक बहिष्कार और संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है (देसाई और कुलकर्णी,2018)।

ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि दलित बच्चों को विद्यालयों में अलग बैठाना, मध्याह्न भोजन वितरण में भेदभाव करना, तथा शिक्षकों द्वारा उपेक्षापूर्ण व्यवहार जैसी समस्याएँ अब भी विद्यमान हैं, जो उनकी शैक्षिक प्रगति को बाधित करती हैं। जातिगत असमानता का एक प्रमुख कारण आर्थिक विषमता भी है, क्योंकि निम्न जातियों का बड़ा भाग ऐतिहासिक रूप से भूमिहीन, श्रमिक या निम्न आय वर्ग में रहा है, जिसके कारण वे निजी विद्यालयों, कोचिंग संस्थानों, डिजिटल संसाधनों और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुविधाओं तक पहुँच नहीं बना पाते।

परिणामस्वरूप उच्च जातियों के विद्यार्थियों की तुलना में निम्न जातियों के विद्यार्थियों की विद्यालय छोड़ने की दर अधिक रहती है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आंकड़े दर्शाते हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों में माध्यमिक और उच्च शिक्षा स्तर पर ड्रॉपआउट दर सामान्य वर्ग की तुलना में कहीं अधिक है (एनएसएसओ, 2021)। समाजशास्त्री पियरे बोरदियो के सांस्कृतिक पूँजी सिद्धांत के अनुसार उच्च सामाजिक समूह अपने बच्चों को भाषा, व्यवहार, सांस्कृतिक संसाधन और शैक्षणिक वातावरण के रूप में अतिरिक्त लाभ प्रदान करते हैं, जबकि निम्न जातीय समूहों के बच्चे इन संसाधनों से वंचित रहते हैं (बूर्दियू2012)। भारतीय संदर्भ में यह अंतर और अधिक गहरा हो जाता है, क्योंकि जाति केवल आर्थिक स्थिति ही नहीं, बल्कि सामाजिक सम्मान और आत्मविश्वास को भी प्रभावित करती है। निम्न जाति के विद्यार्थी प्रायः आत्महीनता, सामाजिक अपमान और पहचान संकट से गुजरते हैं, जिससे उनकी शैक्षिक उपलब्धियाँ प्रभावित होती हैं।

उच्च शिक्षा संस्थानों में भी जातिगत असमानता दिखाई देती है। यद्यपि आरक्षण नीति ने विश्वविद्यालयों और व्यावसायिक संस्थानों में प्रतिनिधित्व बढ़ाया है, फिर भी प्रवेश के बाद सामाजिक स्वीकृति और समान अवसर का अभाव बना रहता है। कई प्रतिष्ठित संस्थानों में दलित और आदिवासी छात्रों के साथ भेदभाव, मानसिक उत्पीड़न तथा अलगाव की घटनाएँ सामने आती रही हैं। रोहित वेमुला प्रकरण ने यह उजागर किया कि उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत पूर्वाग्रह किस प्रकार विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य और अस्तित्व को प्रभावित कर सकते हैं।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 4, January 2026 Impact Factor: 7.67

जातिगत असमानता का प्रभाव केवल प्रवेश तक सीमित नहीं, बल्कि पाठ्यक्रम, भाषा और संस्थागत संस्कृति में भी परिलक्षित होता है। अधिकांश विद्यालयी पाठ्यपुस्तकों में लंबे समय तक उच्च जातीय दृष्टिकोण का वर्चस्व रहा, जिससे निम्न जातीय समुदायों के इतिहास, संघर्ष और योगदान को पर्याप्त स्थान नहीं मिला। इससे शिक्षा व्यवस्था स्वयं सामाजिक असमानताओं को पुनरुत्पादित करने का माध्यम बन जाती है। डॉ. भीमराव आंबेडकर ने शिक्षा को सामाजिक मुक्ति का सबसे प्रभावी हथियार बताया था और कहा था कि "शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो" यह संदेश आज भी जातिगत असमानताओं के विरुद्ध प्रासंगिक है।

स्वतंत्र भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, छात्रवृत्ति योजनाएँ, आरक्षण नीति, मध्याह्न भोजन योजना, आवासीय विद्यालय और विशेष कोचिंग कार्यक्रम जैसे अनेक कदम उठाए गए हैं, जिनका उद्देश्य जातिगत विषमता को कम करना है। फिर भी इन योजनाओं के क्रियान्वयन में क्षेत्रीय असमानता, भ्रष्टाचार, सामाजिक पूर्वाग्रह और प्रशासनिक उदासीनता बड़ी बाधाएँ हैं। डिजिटल शिक्षा के विस्तार ने भी नई चुनौतियाँ उत्पन्न की हैं, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा के लिए आवश्यक स्मार्टफोन, इंटरनेट और तकनीकी दक्षता निम्न जातीय गरीब परिवारों के पास सीमित है, जिससे डिजिटल विभाजन और गहरा हुआ है। जाति आधारित शैक्षिक असमानता केवल संसाधनों की समस्या नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना की भी समस्या है।

जब तक समाज में जातिगत श्रेष्ठता और हीनता की मानसिकता बनी रहेगी, तब तक विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में वास्तविक समानता स्थापित नहीं हो सकेगी। शिक्षा संस्थानों को केवल प्रवेश देने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि समावेशी वातावरण, संवेदनशील शिक्षक प्रशिक्षण, भेदभाव विरोधी तंत्र और सामाजिक न्याय आधारित पाठ्यक्रम विकसित करने चाहिए। समतामूलक शिक्षा तभी संभव है जब जातिगत पहचान व्यक्ति की शैक्षिक संभावनाओं का निर्धारक न बने।

शिक्षा नीति, सामाजिक सुधार और संवैधानिक मूल्यों के समन्वय से ऐसी व्यवस्था निर्मित की जाए जिसमें प्रत्येक बच्चा, चाहे उसकी जाति कोई भी हो, समान सम्मान, अवसर और गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त कर सके।भारतीय समाज में जाति शिक्षा के अवसरों को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। निम्न जातियों के विद्यार्थियों को विद्यालयों में भेदभाव, संसाधनों की कमी तथा सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है।

1. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों की विद्यालय छोड़ने की दर अधिक है।
2. ग्रामीण क्षेत्रों में दलित बच्चों को विद्यालयों में पृथक बैठाने जैसी घटनाएँ आज भी देखी जाती हैं।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 4, January 2026
Impact Factor: 7.67

तालिका 1: जाति आधारित शैक्षिक असमानता

सामाजिक समूह	साक्षरता दर (%)	उच्च शिक्षा में भागीदारी (%)
सामान्य वर्ग	82	28
ओबीसी	68	18
एससी	60	12
एसटी	54	9

लिंग और शिक्षा में असमानता

लड़कियों की शिक्षा पर सामाजिक मान्यताएँ, बाल विवाह, घरेलू कार्यभार और सुरक्षा संबंधी चिंताएँ नकारात्मक प्रभाव डालती हैं।

1. ग्रामीण भारत में माध्यमिक स्तर पर लड़कियों का ड्रॉपआउट अधिक है।
2. STEM शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी अभी भी कम है।

तालिका 2: लिंग आधारित शिक्षा असमानता

स्तर	लड़के नामांकन (%)	लड़कियाँ नामांकन (%)
प्राथमिक	95	92
माध्यमिक	88	79
उच्च शिक्षा	52	43

वर्ग और शिक्षा में असमानता

आर्थिक वर्ग शिक्षा की गुणवत्ता और पहुँच दोनों को प्रभावित करता है। उच्च वर्ग निजी विद्यालयों, कोचिंग और डिजिटल संसाधनों तक पहुँच रखते हैं, जबकि निम्न वर्ग सरकारी विद्यालयों पर निर्भर रहता है।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 4, January 2026 Impact Factor: 7.67

1. निजी विद्यालयों में संसाधन अधिक, सरकारी विद्यालयों में कम।
2. डिजिटल विभाजन वर्गीय असमानता को और बढ़ाता है।

अंतःसंबंध: जाति, लिंग और वर्ग

जाति, लिंग और वर्ग स्वतंत्र कारक नहीं हैं; ये परस्पर अंतःक्रियात्मक हैं। उदाहरणतः दलित लड़कियाँ तिहरी वंचना का सामना करती हैं, जातिगत, लैंगिक और आर्थिक।

सरकारी नीतियाँ और पहल

भारतीय सरकार ने अनेक योजनाएँ लागू की हैं:

1. शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009)
2. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ
3. मध्याह्न भोजन योजना
4. छात्रवृत्ति योजनाएँ

इन पहलों के बावजूद कार्यान्वयन में असमानता बनी हुई है।

निष्कर्ष

शिक्षा में समानता सुनिश्चित करने के लिए केवल नीतिगत हस्तक्षेप पर्याप्त नहीं; सामाजिक मानसिकता में परिवर्तन भी आवश्यक है। समावेशी शिक्षा तभी संभव है जब जाति, लिंग और वर्ग आधारित भेदभाव समाप्त हों।

संदर्भ सूची

1. आज़म, एम., और किंगडन, जी. जी. (2013). क्या भारत में लड़कियाँ 'अधिक पसंदीदा' लिंग हैं? शिक्षा व्यय के घरेलू बँटवारे की पुनर्समीक्षा। विश्व विकास, 42, 143–164. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2012.06.003
2. एन.एस.एस.ओ. (2021). भारत में शैक्षिक सांख्यिकी। भारत सरकार।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 4, January 2026 Impact Factor: 7.67

3. कमल, यू., और रोलुआपुइया. (2025). भारत में शैक्षिक असमानता और घरेलू गतिशीलता: जातिगत पूंजी की भूमिका की पड़ताल। सामाजिक और आर्थिक विकास पत्रिका, 20(1), 1–23. https://doi.org/10.1177/09731741241291689
4. किंगडन, जी. जी. (2017). भारत में स्कूली शिक्षा की प्रगति। ऑक्सफ़ोर्ड आर्थिक नीति समीक्षा, 23(2), 168–195. https://doi.org/10.1093/oxrep/grm015
5. गर्ग, एम. के., चौधरी, पी., और कंचन, एम. आई. के. एस. (2022). भारत में शैक्षिक असमानता का एक अवलोकन: सामाजिक और जनसांख्यिकीय कारकों की भूमिका। शिक्षा के क्षेत्र में नई दिशाएँ, 7, 871043. https://doi.org/10.3389/feduc.2022.871043
6. चनाना, के. (2017). वैश्वीकरण, उच्च शिक्षा और लिंग: भारतीय महिला छात्रों की बदलती विषय पसंद। आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 42(7), 590–598. https://doi.org/10.2307/4419288
7. जेफ़री, आर., जेफ़री, पी., और जेफ़री, सी. (2018). आज़ादी के बिना डिग्रियाँ? उत्तरी भारत में शिक्षा, पुरुषत्व और बेरोज़गारी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 14(2), 67–89. https://doi.org/10.11126/stanford/9780804755470.001.0001
8. टियरनी, डब्ल्यू. जी., सभरवाल, एन. एस., और मालिश, सी. एम. (2019). असमान संरचनाएँ: भारतीय उच्च शिक्षा में वर्ग और जाति। गुणात्मक जाँच, 25(5), 458–469. https://doi.org/10.1177/1077800418817836
9. ड्रेज़, जे., और किंगडन, जी. जी. (2011). ग्रामीण भारत में स्कूली भागीदारी। Review of विकास अर्थशास्त्र, 5(1), 1–24. https://doi.org/10.1111/1467-9361.00103
10. तिलक, जे. बी. जी. (2015). भारत में उच्च शिक्षा कितनी समावेशी है? सामाजिक परिवर्तन, 45(2), 185–223. https://doi.org/10.1177/0049085715574188
11. दुर्खीम, ई. (2010). शिक्षा और समाजशास्त्र। फ्री प्रेस।
12. देशपांडे, ए. (2011). जाति का व्याकरण: समकालीन भारत में आर्थिक भेदभाव। ऑक्सफ़ोर्ड विकास अध्ययन, 39(2), 163–180. https://doi.org/10.1080/13600818.2011.568999
13. देसाई, एस., और कुलकर्णी, वी. (2018). भारत में बदलती शैक्षिक असमानताएं। जनसांख्यिकी, 45(2), 245-270। https://doi.org/10.1353/dem.0.0001

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 4, January 2026
Impact Factor: 7.67

14. नंबिसन, जी. बी. (2010). स्कूलों में बहिष्कार और भेदभाव: दलित बच्चों के अनुभव। भारतीय दलित अध्ययन संस्थान पत्रिका, 5(1), 45–62. https://doi.org/10.1177/097318491000500104
15. नाइट, डी. के., और डैश, बी. सी. (2022). जाति, वर्ग और विकास के अनुभव: आधुनिक भारत में सामाजिक असमानता/समानता पर विमर्श। जाति: सामाजिक बहिष्कार पर एक वैश्विक पत्रिका, 4(4), 233–248. https://doi.org/10.1177/25166026221123482
16. बॉर्डियू, पी. (2012). पूंजी के रूप। जे. रिचर्डसन (संपादक) द्वारा संपादित, शिक्षा के समाजशास्त्र के लिए सिद्धांत और अनुसंधान की पुस्तिका (पृष्ठ 241-258)। ग्रीनवुड।
17. बोरूआ, वी. के. (2012). सामाजिक पहचान और शैक्षिक उपलब्धि: भारत में जाति और धर्म की भूमिका। विकास अध्ययन पत्रिका48(7), 887–903. https://doi.org/10.1080/00220388.2011.621945
18. मुरलीधरन, के., और प्रकाश, एन. (2017). स्कूल तक साइकिल से: भारत में लड़कियों के लिए माध्यमिक स्कूल में नामांकन बढ़ाना। अमेरिकन इकोनॉमिक जर्नल: एप्लाइड इकोनॉमिक्स 9(3), 321–350. https://doi.org/10.1257/app.20160004
19. यू.डी.आई.एस.ई.+ (2022). एकीकृत जिला सूचना प्रणाली शिक्षा रिपोर्ट। शिक्षा मंत्रालय, भारत।
20. रेड्डी, ए. बी., शुक्ला, पी. के., अग्रवाल, एम., और सिंह, (2026). जाति, वर्ग, शहर और चुनाव: शहरी भारत में जाति-आधारित स्कूली अलगाव को समझना। शहरी अध्ययन। https://doi.org/10.1177/00420980251407970
21. श्रीवास्तव, आर. (2024). जाति में वर्ग: भारत में बच्चों में मानव पूंजी निवेश में असमानताएँ। शैक्षिक विकास का अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, 106, 103004. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2024.103004
22. सिंह, ए., और मुखर्जी, एस. (2018). भारत में लिंग, जाति और शिक्षा: स्कूलों से ड्रॉप-आउट का एक कोहोर्ट-वार अध्ययन। सामाजिक स्तरीकरण और गतिशीलता में अनुसंधान, 58, 54–68. https://doi.org/10.1016/j.rssm.2018.10.002
23. सुंदरम, वी., और वैनेमैन, आर. (2018). भारत में साक्षरता में लैंगिक अंतर: महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी के साथ दिलचस्प संबंध। विश्व विकास, 36(1), 128–143. https://doi.org/10.1016/j.2017.02.017

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 4, January 2026
Impact Factor: 7.67

24. सेन, ए. (2012). विकास स्वतंत्रता के रूप में। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
25. स्कारिया, एस. (2014). क्या जाति और वर्ग असमानता को परिभाषित करते हैं? केरल के एक गाँव में शिक्षा की पुनर्समीक्षा। समकालीन शिक्षा संवाद, 11(2), 153–177. https://doi.org/10.1177/0973184914529012